

स्थानीय सरकार

प्रलिस के लयः

स्थानीय सरकारें, 73वाँ संवधान संशोधन, 74वाँ संशोधन अधनियम (1992) ।

मेन्स के लयः

पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय नकिय।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि देश भर के राज्य चुनाव आयोगों द्वारा हर पाँच वर्ष में स्थानीय नकियों के चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्वों को अच्छे से नभाना चाहिये ।

- चुनाव आयोग चुनाव कराने की जल्दबाज़ी के कारण परसिमन की प्रक्रिया या नए वार्डों के गठन जैसे आधारों को **रद्द नहीं कर सकता है** ।
- न्यायालय ने पाया कि **23,000 ग्रामीण स्थानीय नकियों** के अलावा **मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय नकियों** में **2019-2020 के बाद से चुनाव नहीं हुए** ।

स्थानीय सरकार:

- **परचिय:**
 - स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय नकियों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं ।
 - स्थानीय स्वशासन में **ग्रामीण और शहरी** दोनों सरकारें शामिल हैं ।
 - यह सरकार का **तीसरा स्तर** है ।
 - स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं - **ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ** ।
- **ग्रामीण स्थानीय नकिय:**
 - पंचायती राज संस्था (PRIs) भारत में **ग्रामीण स्थानीय स्वशासन** की एक प्रणाली है ।
 - पीआरआई को 73वें संवधान संशोधन अधनियम, 1992 के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिये संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया ।
 - इस अधनियम ने भारत के संवधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है । इस भाग में 'पंचायतों' के लिये **अनुच्छेद 243 से 243-O तक** गए प्रावधान शामिल हैं ।
 - इसके अलावा अधनियम ने संवधान में एक नई ग्यारहवी अनुसूची भी जोड़ी है । इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं । यह अनुच्छेद **243-G** से संबंधित है ।
 - अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में PRIs ने अपने अस्तित्व के 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं । हालाँकि ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है ।
- **'शहरी स्थानीय नकिय:**
 - **शहरी स्थानीय नकियों** की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई है ।
 - भारत में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय नकिय वदियमान हैं- नगर नगिम, नगर पालिका, अधसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी ।
 - केंद्रीय स्तर पर 'नगरीय स्थानीय शासन या नकिय' का वषिय नमिनलखिति तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है ।
 - वर्ष 1985 में शहरी विकास मंत्रालय (अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था ।
 - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय ।
 - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय ।
 - वर्ष 1992 में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वाँ संशोधन अधनियम पी.वी. नरसमिहा राव की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जो 1 जून, 1993 को लागू हुआ ।

- इसके द्वारा संवधान में भाग IX-A को जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं।
- जोड़ा गया भाग IX-A और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं।
- संवधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 वषिय शामिल हैं तथा ये अनुच्छेद 243-W से संबंधित हैं।

73वें संवधान संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

■ अनविरय प्रावधान:

- ग्राम सभाओं का गठन।
- ज़िला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रस्तरीय पंचायती राज संरचना का नरिमाण।
- लगभग सभी पद, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये।
- ज़िला एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष नरिवाचन द्वारा भरा जाना चाहिये।
- पंचायतों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में और पंचायतों में महिलाओं के लिये एक-तह्राई सीटें आरक्षणित होनी चाहिये।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन कथिा जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष है, यदा इन्हें पहले भंग कर दथिा जाता है, तो छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे।
- प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वृत्त आयोग का गठन कथिा जाना।

■ स्वैच्छक प्रावधान:

- इन नकियों में केंद्र और राज्य वधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना।
- पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क आदि के संबंध में वृत्तीय अधिकार दथिे जाने चाहिये तथा पंचायतों को स्वायत्त नकिय बनाने का प्रयास कथिा जाएगा।

74वें संशोधन अधनियम की मुख्य विशेषताएँ:

■ अनविरय:

- छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर परिषदों व नगर नगिमों का गठन।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये शहरी स्थानीय नकियों में सीटों का आरक्षण मोटे तौर पर उनकी आबादी के अनुपात में।
- एक-तह्राई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षणित;
- पंचायती राज नकियों में चुनाव कराने के लिये गठित राज्य नरिवाचन आयोग (73वाँ संशोधन) शहरी स्थानीय स्वशासी नकियों के लिये भी चुनाव कराएगा।
- पंचायती राज नकियों के वृत्तीय मामलों से नपिटने के लिये गठित राज्य वृत्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी नकियों के वृत्तीय मामलों को भी देखता है।
- शहरी स्थानीय स्वशासी नकियों का कार्यकाल पाँच वर्ष नरिधारित कथिा गया है और पहले वधितन के मामले में छह महीने के भीतर नए चुनाव होते हैं।

■ स्वैच्छक:

- इन नकियों में संघ और राज्य वधानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना।
- पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रदान करना।
- करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों आदि के संबंध में वृत्तीय अधिकार देना।
- नगर नकियों को स्वायत्त बनाना और इन नकियों को इस अधनियम के माध्यम से संवधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में शामिल कुछ या सभी कार्यों को करने और/या आर्थिक वकिस के लिये योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ प्रदान करना।

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन कसि गुण की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? (2017)

- संघवाद
- लोकतांत्रिक वकिंदरीकरण
- प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

स्रोत: द हट्ट

